

दिनांक 09.01.2018 को समिति कक्ष, राजविअ , तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में पूर्वाहन 11:00 बजे "नदियों को जोड़ने के लिए कार्य बल के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की चौथी बैठक का कार्यवृत्त।

"नदियों को जोड़ने के लिए कार्य बल के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की चौथी बैठक भारत सरकार के पूर्व सचिव और समूह के अध्यक्ष डॉ प्रदीप्तो घोष की अध्यक्षता में दिनांक 09.01.2018 (मंगलवार) को सुबह 11:00 बजे राजविअ के समिति कक्ष, तीसरी मंजिल, पालिका भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों की सूची अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

प्रारंभ में श्री घोष ने सभी सदस्यों, आमंत्रित सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने नीति आयोग के सदस्य की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की और श्री के पी गुप्ता को सलाह दी कि यदि श्री धीरज नैयर, ओएसडी को वित्तीय समूह की बैठकों में भाग लेने का समय नहीं मिल रहा है, तो आयोग के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के लिए कार्य बल के अध्यक्ष से नीति आयोग को एक डीओ पत्र भेजें। उन्होंने समूह के सदस्य सचिव श्री के पी गुप्ता से अनुरोध किया कि वे कार्यसूची के विषयों पर एक-एक करके चर्चा करें।

मद संख्या 4.1 वित्तीय पहलू पर दिनांक 08.12.2017 को आयोजित समूह की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 08.12.2017 को नई दिल्ली में आयोजित नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह की तीसरी बैठक के कार्यवृत्त को राजविअ के पत्र दिनांक 2 जनवरी, 2018 के माध्यम से सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के बीच परिचालित किया गया था। चूंकि किसी से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी। सदस्य, दिनांक 08.12.2017 को आयोजित तीसरी बैठक के कार्यवृत्त की परिचालित के रूप में पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 4.2 राजकोषीय संसाधनों के प्रक्षेपण पर नीति आयोग द्वारा प्रस्तुतीकरण

इस मद को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि नीति आयोग के प्रतिनिधि किसी अन्य व्यस्तता के कारण बैठक में भाग लेने के लिए नहीं आ सके। तथापि, समूह के अध्यक्ष की इच्छा थी कि एक डी.ओ. यदि श्री धीरज नैयर, ओएसडी, को वित्तीय समूह की बैठकों में भाग लेने का समय नहीं मिल रहा है, तो आयोग के किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्त करने के लिए अध्यक्ष, कार्य बल का पत्र नीति आयोग को जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि इस तरह की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ-साथ नीतिगत निर्णय के लिए सरकारी वित्त पोषण की सीमा जानने के लिए नीति आयोग की भागीदारी बहुत आवश्यक है।

मद संख्या 4.3 भारतीय बैंकों / वित्तीय संस्थानों से आईएलआर कार्यक्रम के लिए धन के संभावित प्रवाह के अनुमानों पर यस बैंक द्वारा प्रस्तुति,

श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, रणनीतिक सरकारी सलाहकार, यस बैंक, नई दिल्ली (श्री राणा कपूर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए) ने कहा कि उन्हें प्रस्तुति को अंतिम रूप देने के लिए अभी भी 8-10 दिनों की आवश्यकता है। तदनुसार, अध्यक्ष ने उन्हें अगली बैठक में अपनी प्रस्तुति देने की अनुमति दी। तथापि, उन्होंने श्री केपी गुप्ता को अपनी प्रस्तुति पहले से भेजने का अनुरोध किया, ताकि इसे सभी सदस्यों को परिचालित किया जा सके। उन्होंने यस बैंक के प्रतिनिधि को सलाह दी कि वे डॉ दासगुप्ता के

साथ संपर्क में रहें।

मद संख्या 4.4 महानदी-गोदावरी लिंक का लागत विश्लेषण और संपूर्ण आईएलआर परियोजना की लागत पर इसका प्रभाव (राजविअ द्वारा प्रस्तुति)

श्री एम.के. सिन्हा, वरिष्ठ सलाहकार, राजविअ ने पिछली बैठक के सुझावों के आधार पर महानदी-गोदावरी (एमजी) लिंक के लागत विश्लेषण और आईएलआर परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। उनकी प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-4.4.1 के रूप में संलग्न है। समूह द्वारा यह नोट किया गया था कि पिछले अनुमानों के संबंध में कुल लागत में कमी आई है क्योंकि लिंक अनुसार सिंचाई और बिजली लाभ का कुल योग एनपीपी (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना) के तहत अनुमानित लाभ से कम है। प्रस्तुति के दौरान, आईएलआर परियोजनाओं की कुल लागत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे:

- (i) श्री के.पी. गुप्ता ने बताया कि एमएसटीजी, जीडीएस और एसएम लिंक के माध्यम से महानदी नदी में गिराए जा रहे ब्रह्मपुत्र जल (लगभग 14 बीसीएम) से सिंचाई लाभ (हेक्टेयर के संदर्भ में) की योजना राजविअ द्वारा नहीं बनाई गई है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि एमएसटीजी, जीडीएस और एसएम लिंक के माध्यम से महानदी नदी में गिराए जा रहे ब्रह्मपुत्र जल (लगभग 14 बीसीएम) से सिंचाई लाभ (हेक्टेयर के संदर्भ में) का उचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए और सिंचाई विकास की कुल लागत निकालने के लिए कुल लाभों में जोड़ा जाना चाहिए।
- (ii) श्री नवीन कुमार, मुख्य अभियंता (आईएमओ), केन्द्रीय जल आयोग ने बताया कि तीसरी बैठक में, भूमि की लागत को चार गुना (वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार) बढ़ाने और उसके बाद मूल्य सूचकांक, और मूल्य सूचकांक के अनुसार अवशिष्ट लागत लागू करने का सुझाव दिया गया था। यह निर्णय लिया गया कि 2015-16 में महानदी-गोदावरी लिंक परियोजना की लागत निकालने के लिए इस पहलू की जांच की जाए। इस शोधन के बाद सिंचाई विकास की लागत का भारित माध्य निकाला जाना चाहिए।

ऊपर सुझाए गए मामूली सुधार करने के बाद, आईएलआर परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत पर काम किया जाना चाहिए और अगली बैठक में आईएलआर परियोजनाओं की अंतिम लागत पर प्रस्तुति दी जानी चाहिए।

मद संख्या 4.5 समूह के काम की प्रगति की समीक्षा और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना।

अध्यक्ष ने इस एजेंडा मद पर एक प्रस्तुतिकरण दिया। उनकी प्रस्तुति की प्रति अनुलग्नक-4.5.1 में संलग्न है अपनी प्रस्तुति के दौरान, उन्होंने संदर्भ की शर्तों के संदर्भ में समूह को सौंपे गए कार्यों के विभिन्न विषयों को विस्तार से बताया। उन्होंने प्रस्तुतिकर्ता (अभिकरणों) की भी पहचान की जिन्हें विभिन्न विषयों पर काम करने के लिए सौंपा जा सकता है। सदस्यों से अनुरोध है कि वे अगली बैठक में प्रस्तावित कार्य कार्यक्रम के संबंध में अपनी टिप्पणी दें, जब कार्य कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा सकता है। उन्होंने प्रस्तुतिकर्ता के अलावा मानव सम्पदा की भूमिका पर जोर दिया। बैठक में, फीडबैक इन्फ्रास्ट्रक्चर के श्री विनायक चटर्जी और डॉ प्रदीप सिंह, पूर्व प्रोफेसर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (यस बैंक से एकत्र किए जाने वाले संपर्क विवरण) के नामों को निजी क्षेत्रों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) के लिए विशिष्ट फंडिंग मॉडल (पीपीपी आदि) पर अगली बैठक में

प्रस्तुति देने और आईएलआर लिंक में भागीदारी और विभिन्न मॉडलों के संबंध में जोखिम शमन के लिए मानव सम्पदा के रूप में पहचाना गया।

आईएलआर सेवाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारण/वार्ता के सिद्धांतों आदि जैसे अन्य विषयों पर प्रस्तुति देने के लिए कुछ अतिरिक्त मानव सम्पदा की पहचान उचित समय पर की जा सकती है।

मद संख्या 4.6 अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मामला

(i) समूह के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि समूह का कार्यकाल शीघ्र ही पूरा होने जा रहा है और इसलिए श्री के.पी.गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), राजविअ को समूह के कार्यकाल को छह महीने और बढ़ाने के लिए मामले को संसाधित करने का सुझाव दिया। समूह ने अभी तक बहुत सारे काम किए हैं, हालांकि इसकी अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं।

(ii) सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श के बाद, अगली बैठक अर्थात् वित्तीय पहलुओं पर समूह की 5वीं बैठक 1 फरवरी, 2018 को 14.30 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक-1

दिनांक 09 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित "नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के तहत वित्तीय पहलुओं पर समूह" की चौथी बैठक में प्रतिभागियों की सूची।

1.	डॉ प्रोदिप्तो घोष, भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईएलआर के लिए टास्क फोर्स के सदस्य और प्रतिष्ठित शोधर्त्थी, टेरी, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्री नवीन कुमार मुख्य अभियंता (आईएमओ), केन्द्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	सदस्य
3.	श्री केपी गुप्ता निदेशक (तकनीकी), राजविअ , नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
4.	श्री भूपेश राठौर, अध्यक्ष, रणनीतिक सरकार ,सलाहकार, यस बैंक लिमिटेड नई दिल्ली	श्री राणा कपूर , प्रबंध निदेशक और सीईओ, यस बैंक लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करते हुए
5.	श्री राज कुमार पचौरी, मुख्य अभियंता (पीपीओ), केन्द्रीय जल आयोग , नई दिल्ली	विशेष आमंत्रित सदस्य
	राजविअ के अधिकारी	
6.	श्री अनिल कुमार जैन,	

	उप निदेशक (एस सी आई एल आर), नई दिल्ली	
7.	श्री एम के सिन्हा वरिष्ठ सलाहकार, नई दिल्ली	
8.	श्री आर के अग्रवाल, सलाहकार, नई दिल्ली	

राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण द्वारा

वित्तीय समूह की चौथी बैठक के लिए आईएलआर परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत (संशोधित) पर प्रस्तुति

आईएलआर कार्यक्रम की अतिरिक्त लागत - पहला अनुमान (दूसरी बैठक में चर्चा की गई)

क्र. संख्या	आई एल आर कार्यक्रम के घटक	परिकल्पित लाभ	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1.	सिंचाई	35 मिलियन हेक्टेयर	2.8 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या 0.028 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर	9.8 लाख करोड़ रुपये
2.	जल विद्युत	34,000 मेगावाट	8 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट	2.72 लाख करोड़ रुपये
3.	पीने का पानी	895 एमसीएम +	प्रति एमसीएम 3.32 करोड़ रुपये	2972 करोड़ रुपये या 0.03 लाख करोड़
	कुल लागत			12.55 लाख करोड़ रुपये

नोट- 1 पहला अनुमान केबीएल परियोजना (अनुमोदित) के सिंचाई विकास की इकाई लागत , केबीएल परियोजना (अनुमोदित) के विद्युत उत्पादन की औसत इकाई लागत और दमनगंगा-पिंजाल लिंक परियोजना (अनुमोदित) पर आधारित था ।

2. अन्य लिंकों के जल आपूर्ति घटक की लागत को इसकी लागत के रूप में नहीं माना जाता है, इसे सिंचाई घटक में शामिल नहीं किया गया है ।

3. लिया लाभ एनपीपी प्रक्षेपण पर आधारित हैं

आई एल आर कार्यक्रम की अतिरिक्त लागत -दूसरा अनुमान (तीसरी बैठक में की गई चर्चा)

क्र संख्या	आई एल आर कार्यक्रम के घटक	परिकल्पित लाभ	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1(क)	पृष्ठ सिंचाई	25 मिलियन हेक्टेयर	3.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या 0.035 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर	8.75 लाख करोड़ रुपये
1(ख)	भूजल के माध्यम से सिंचाई	10 मिलियन हेक्टेयर	1.0 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या 0.01 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर	1.00 लाख करोड़ रुपये (गिरा)
2.	जल विद्युत	34,000 मेगावाट	6.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट	रु.2.11 लाख करोड़
3.	पीने का पानी	895 एमसीएम +	प्रति एमसीएम 3.32 करोड़ रुपये	0.03 लाख करोड़
	कुल लागत			11.89 लाख करोड़ रुपये

दूसरे अनुमान के लिए आधार

1. एनपीपी के अनुसार लाभ (राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना)
2. सिंचाई घटक की कुल लागत की गणना करते समय, तीन परियोजनाओं नामतः केन-बेतवा, पी-टी-एन और महानदी-गोदावरी लिंक परियोजनाओं की सिंचाई विकास की औसत इकाई लागत पर विचार किया गया।
3. विद्युत घटक की कुल लागत की गणना करते समय, 2585 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की इकाई लागत संकोश एच.ई. भूटान में परियोजना (सीईए द्वारा स्वीकृत) जो 6.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, पर विचार किया गया है।

तीसरी बैठक के निर्णय

- आईएलआर परियोजना की कुल लागत को पूरा करने के लिए सिंचाई विकास और बिजली विकास की लिंक-अनुसार लागत पर विचार किया जाना चाहिए
- आईएलआर परियोजनाओं के लिए भूजल के माध्यम से सिंचाई विकास की लागत पर विचार नहीं किया जाएगा
- एमजी लिंक की लागत (2003-04 पी.एल. पर) को 2015-16 में पी.एल. मूल्य सूचकांक के आधार पर अपग्रेड किया जाना चाहिए।
- सिंचाई विकास की इकाई लागत तीन परियोजनाओं के भारित माध्य के आधार पर तय की जानी चाहिए, नामतः, केबीएल, पीटीएनएल और एमजीएल सरल अंकगणितीय माध्य के स्थान पर।
- बिजली परियोजनाओं की लागत रु.8.00 करोड़/मेगावाट परियोजनाओं के उत्पादन के लिए ली जानी चाहिए < 500 मेगावाट और 6.2 करोड़/मेगावाट परियोजनाओं के उत्पादन के लिए > 500 मेगावाट

निर्णयों का कार्यान्वयन

- सिंचाई विकास और विद्युत विकास की लिंक-वार लागत पर आईएलआर परियोजना की कुल लागत (किया गया, कुल सिंचाई-17.03 एम हैक्टेयर, कुल बिजली-29750 मेगावाट) को समाप्त करने पर विचार किया जाना चाहिए)
- भूजल के माध्यम से सिंचाई विकास की लागत को आईएलआर परियोजनाओं के लिए नहीं माना जाएगा (इसमें शामिल नहीं)
- एम-जी लिंक की लागत (2003-04 पी.एल.) मूल्य सूचकांक के आधार पर 2015-16 पी.एल. में अपग्रेड किया जाना चाहिए। (2003-04 में मूल्य सूचकांक 463 था और 2015-16 में 1982-83 के आधार वर्ष के मुकाबले 1081 था)
- सिंचाई विकास की इकाई लागत को सरल अंकगणितीय माध्य के स्थान पर तीन परियोजनाओं, नामतः, केबीएल, पीटीएनएल और एमजीएल के भारित माध्य पर निकाला जाना चाहिए।
- **500 मेगावाट से कम की परियोजनाओं के लिए बिजली परियोजनाओं की लागत 8.00 करोड़ रुपये/मेगावाट और परियोजनाओं के उत्पादन के लिए 6.2 करोड़ रुपये/मेगावाट के रूप में ली जानी चाहिए (निम्नलिखित)**

भारित माध्य सिंचाई विकास की लागत

एस.एन.	परियोजना का नाम	लाख हेक्टेयर में वार्षिक सिंचाई	सिंचाई विकास की लागत
1.	केन बेतवा (पी एच -I)	6.36	रु.2.74 लाख/ हेक्टेयर
2.	पार-तापी-नर्मदा	2.32	रु.4.32 लाख / हेक्टेयर
3.	महानदी-गोदावरी	4.43	रु.4.165 लाख/ हेक्टेयर
	औसत लागत		रु.3.74 लाख/ हेक्टेयर
	भारित माध्य लागत		रु.3.50 लाख / हेक्टेयर

तीसरे एमटीजी में निर्णय के अनुसार आईएलआर कार्यक्रम की संशोधित अतिरिक्त लागत

एस.एन.	आई एल आर प्रोग्राम के घटक	परिकल्पित लाभ	प्रति इकाई लागत	कुल लागत
1(क)	पृष्ठ सिंचाई	17.03 मिलियन हेक्टेयर	3.5 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर या 0.035 करोड़ रुपये प्रति हेक्टेयर	5.96 लाख करोड़ रुपये
2. (क)	जल विद्युत	27,962 मेगावाट	6.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट	रु.1.73 लाख करोड़
2.(ख)	जल विद्युत	1608	8.0 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट	रु.0.13 लाख करोड़
3.	पीने का पानी	895 एमसीएम +	प्रति एमसीएम 3.32 करोड़ रुपये	0.03 लाख करोड़
	कुल लागत			रु.07.85 लाख करोड़

नोट- 1 दमनगंगा-पिंजाल लिंक केवल जल आपूर्ति परियोजना है। अन्य लिंक परियोजनाओं के संबंध में जल आपूर्ति घटक की लागत को सामान्यतः सिंचाई घटक में शामिल किया जाता है।

निष्कर्ष

अतिरिक्त लागत मुख्य रूप से निम्नलिखित दो कारणों से कम हुई है:

* लिंक अनुसार विचार करने पर सिंचाई लाभों में 25 मिलियन हेक्टेयर से 17.03 मिलियन हेक्टेयर तक की कमी।

* परियोजनाओं के लिए बिजली उत्पादन की कम लागत (6.2 करोड़ / मेगावाट) पर विचार < 500 मेगावाट की अधिकांश परियोजनाएं भूटान और नेपाल में हैं।

धन्यवाद

नदियों को आपस में जोड़ना:
आईएलआर पर कार्यबल के वित्त समूह का प्रस्तावित
कार्यक्रम
प्रोदिप्तो घोष, पीएच.डी 09 जनवरी 2018

वित्त समूह के टीओआर

1. 2002 में गठित पूर्ववर्ती कार्य बल के वित्त से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करना।
2. प्रत्येक लिंक परियोजना के लिए वित्त पोषण तंत्र का सुझाव देना।
3. केन-बेतवा की तर्ज पर एनपीपी के कुछ आईबीडब्ल्यूटी लिंक को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने के विकल्प का अध्ययन करना।
4. संबंधित लाभार्थी राज्यों द्वारा संपर्क परियोजनाओं की लागत-हिस्सेदारी का अध्ययन करना और लागत-हिस्सेदारी के लिए आधार/सूत्र का सुझाव देना।
5. उपरोक्त पहलुओं से संबंधित कोई अन्य मामला।

वित्त उपसमूह हेतु प्रस्तावित कार्य योजना

कार्य सं.	कार्य का विषय	विषय के लिए प्रस्तुतकर्ता	टीओआर से संबंधित है क्र.	टिप्पणियां
1	वित्तीय पहलुओं पर पहले की कार्य बल की सिफारिशों की समीक्षा	अध्यक्ष	1	पूर्व के कार्यबल के लिए एनसीईआर की सिफारिशों की समीक्षा पूरी
2	प्रत्येक लिंक की अद्यतन लागत और 2015 की कीमतों पर आईएलआर के लिए कुल	राजविअ	2, 3, 4	प्रथम आदेश अद्यतन पूर्ण हुआ. शोधन चल रहा है। कार्य संख्या 3, 4, 5 के पूरा होने के बाद मूल्यांकन किए जाने वाले आईएलआर के लिए समग्र समय सीमा
3	सार्वजनिक वित्त के अनुमान 2048 तक आईएलआर के लिए उपलब्ध होने की संभावना	नीति आयोग	2, 3, 4	?
4	भारतीय वित्तीय संस्थानों से निजी वित्त के अनुमान 2048 तक आईएलआर के लिए उपलब्ध होने की संभावना	यस बैंक + डॉ दीपक दासगुप्ता	2, 4	कार्यप्रणाली पर चर्चा की

कार्य सं	कार्य का विषय	विषय के लिए प्रस्तुतकर्ता	टीओआर से संबंधित है क्र.	टिप्पणियां
5	बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (डब्ल्यूबी, एडीबी, जीसीएफ, ब्रिक्स बैंक, जीसीएफ, आदि) से 2048 तक आईएलआर के लिए वित्त पोषण के अनुमान।	NITI आयोग / श्री सतीश राव + डॉ दीपक दासगुप्ता	2, 4	
6	भारत में सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के लिए उचित परिश्रम आवश्यकताओं की समीक्षा	राजविअ	2, 3, 4	पूरा किया
7	आईएलआर लिंक में निजी क्षेत्र (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की भागीदारी के लिए विशिष्ट वित्तपोषण मॉडल (पीपीपी आदि) की समीक्षा	मानव सम्पदा (ओं) की पहचान की जानी है + यस बैंक	2, 4, 5	प्रत्येक प्रकार के मॉडल/प्रतिभागी के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए जोखिम शमन तंत्र की भी पहचान की जाएगी
8	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (डब्ल्यूबी आदि) के वित्तपोषण मॉडल और उचित परिश्रम आवश्यकताओं की समीक्षा।	मानव सम्पदा की पहचान की जाएगी + श्री सतीश राव + डॉ दीपक दासगुप्ता	2, 4, 5	प्रत्येक वित्तपोषण मॉडल / प्रतिभागी के लिए जोखिम शमन तंत्र पर भी चर्चा की जानी चाहिए

कार्य सं	कार्य का विषय	विषय के लिए प्रस्तुतकर्ता	टीओआर से संबंधित है क्र.	टिप्पणियां
9	आईएलआर सेवाओं (सिंचाई, पेयजल, अंतर्देशीय नेविगेशन, आदि) के लिए टैरिफ निर्धारण / बातचीत के लिए सिद्धांत, और गंतव्य राज्यों और / या केंद्र सरकार द्वारा स्रोत राज्यों को लाभों का भुगतान।	अध्यक्ष + श्री एबी पंड्या + डॉ दीपक दासगुप्ता (+ संसाधन व्यक्ति)	2, 4, 5	आई एल आर टैरिफ नियामक बोर्ड के गठन की संभावना और इसके अधिदेश पर भी चर्चा की जाएगी
10	राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में संभावित घोषणा के लिए लिंक + एमके मित्तल + की पहचान और / या अन्ययस बैंक + डॉ दीपक वित्तपोषण भागीदारों द्वारा भागीदारी के लिए सार्वजनिक वित्त का लाभ उठाने के व्यवहार्य तरीके	अध्यक्ष + एबी पंड्या + एमके मित्तल + डॉ दीपक दासगुप्ता	2, 3, 5	

कार्य सं	कार्य का विषय	विषय के लिए प्रस्तुतकर्ता	टीओआर से संबंधित है क्र	टिप्पणियां
11	लाभार्थी राज्यों द्वारा सह-वित्तपोषण सहित प्रत्येक (प्रकार के) लिंक के लिए वित्तपोषण पैटर्न की पहचान	अध्यक्ष + राजविअ + AB पंड्या + एमके मित्तल + यस बैंक + डॉ दीपक दासगुप्ता	2	
12	वित्त समूह की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना	अध्यक्ष + राजविअ	1, 2, 3, 4, 5	

धन्यवाद